26-02-2024

संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती समारोह को संबोधित किया। गौरतलब है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार, संत रविदास जयंती माघ महीने की पूर्णिमा के अवसर पर मनाई जाती है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- यह समारोह सीर गोवर्धनपुर में BHU के पास संत गुरु रविदास जन्मस्थली मंदिर में आयोजित किया गया था।
- उन्होंने संत रविदास जन्मस्थली के आसपास लगभग 32 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और संत रविदास संग्रहालय के निर्माण की आधारशिला रखी।
- गुरु रविदास का जन्म 1377 ई. में उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर गांव में साधारण परिवार से हुआ था।
- गुरु रविदास, जिन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक हैं।
- वाराणसी में वंचित अछूत चमड़े का काम करने वाली जाति में जन्मे, उनका जीवन और कार्य उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि की चुनौतियों और संघर्षों को गहराई से दर्शाते हैं।

भारत टेक्स 2024

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 26 फरवरी से शुरू होने वाले भारत टेक्स 2024 चार दिवसीय कार्यक्रम है जिसका औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- भारत टेक्स अपने विशाल प्रदर्शनी क्षेत्र के साथ नई दिल्ली में दो स्थानों भारत मंडपम और यशोभूमि में 22 लाख वर्ग फुट से अधिक फैला हुआ है।
- 100 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले खरीदारों की भागीदारी और 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं की उपस्थिति के साथ, यह भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कपड़ा कार्यक्रम बनने की ओर अग्रसर है।
- इस आयोजन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी सहित 46 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे|
- भविष्य के सर्कुलर समाधानों की पहचान के लिए टेक्सटाइल ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज शुरू किया जाएगा|
- यह आयोजन 11 निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए सभी मूल्य श्रृंखला दिग्गजों के बीच सहयोग का एक आदर्श उदाहरण है, जो फार्म से लेकर अंतिम उत्पादों तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर करता है।
- भारत टेक्स प्रदर्शनी में परिधान, घरेलू सामान, फर्श कवरिंग, फाइबर, सूत, धागे, कपड़े, कालीन, रेशम, कपड़ा आधारित हस्तशिल्प, तकनीकी कपड़ा और बहुत कुछ शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 5एफ विजन से प्रेरित होकर इस कार्यक्रम का 'एकीकृत फार्म टू फैशन फोकस', संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर करता है।

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

रायसीना डायलॉग सम्मेलन 2024

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारीकोस मित्सोटाकिस की उपस्थिति में नई दिल्ली में प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित प्रतिष्ठित रायसीना डायलॉग सम्मेलन के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया।
- इस वर्ष कार्यक्रम का थीम "Chaturanga: Conflict, Contest, Cooperate, Create" है जो चल रही वैश्विक अनिश्चितताओं और अशांति के साथ-साथ साझेदारी के माध्यम से अवसरों को भी समाहित करता है।

रायसीना डायलॉग क्या है?

- रायसीना डायलॉग भू-राजनीतिक एवं भू-आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक वार्षिक सम्मेलन है जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (Observer Research Foundation- ORF) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
- इसका प्रारंभ वर्ष 2016 में किया गया था। 2016 में लॉन्च होने के बाद से यह भारत के सबसे हाई-प्रोफाइल भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र मंच के रूप में उभरा है।
- यह यह एक बहु-हितधारक, क्रॉस-सेक्टरल बैठक है जिसमें नीति-निर्माताओं एवं निर्णयकर्त्ताओं, विभिन्न राष्ट्रों के हितधारकों, राजनेताओं, पत्रकारों, उच्चाधिकारियों तथा उद्योग एवं व्यापार जगत के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है।
- इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के विदेश, रक्षा और वित्त मंत्रियों को शामिल किया जाता है।

  रायसीना डायलॉग का मुख्य उद्देश्य एशियाई एकीकरण के साथ-साथ शेष विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं एवं अवसरों की तलाश करना है।
- व्यापक अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत मामलों पर चर्चा करने के लिये नीतिगत, व्यापार, मीडिया और नागरिक समाज से संबंधित वैश्विक नेताओं को प्रति वर्ष रायसीना डायलॉग में आमंत्रित किया जाता है।

भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार ने रणनीतिक अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) दिशानिर्देशों में संशोधन किया, जिससे उपग्रह निर्माण, लॉन्च वाहन निर्माण और जमीनी बुनियादी ढांचे के निर्माण में अधिक विदेशी पूंजी प्रवाह की अनुमति मिल गई।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नीति उपग्रहों, जमीनी खंडों और उपयोगकर्ता खंडों के लिए घटकों और प्रणालियों या उप-प्रणालियों के निर्माण में 100% FDI सुनिश्चित करती है।
- सैटेलाइट विनिर्माण और संचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पादों और ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए 74 प्रतिशत FDI की अनुमति दी गई है। 74 प्रतिशत से अधिक ये गतिविधियाँ सरकारी मार्ग के अंतर्गत आती हैं।
- लॉन्च वाहनों और संबंधित प्रणालियों के विकास और अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने और प्राप्त

करने के लिए स्पेसपोर्ट के निर्माण के लिए, स्वचालित मार्ग के तहत FDI 49 प्रतिशत तय किया गया है।

- इन परिवर्तनों का उद्देश्य भारत में अत्याधुनिक तकनीकों को पेश करना, घरेलू अंतरिक्ष खिलाड़ियों को वैश्विक बड़ी कंपनियों के साथ मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना और अंतरिक्ष संपत्ति निर्माण क्षमताओं में तेजी से वृद्धि के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन, टेलीमेडिसिन, इंटरनेट कनेक्टिविटी में राष्ट्रीय मांगों को पूरा करना है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) क्या होता है?

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है। FDI किसी निवेशक को एक बाहरी देश में प्रत्यक्ष व्यावसायिक खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आर्थिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण चालक होने के साथ ही देश के आर्थिक विकास के लिये एक प्रमुख गैर-ऋण वित्तीय संसाधन भी रहा है।
- यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) से अलग है जहाँ विदेशी संस्था केवल किसी कंपनी के स्टॉक और बॉण्ड खरीदती है। FPI निवेशक को व्यवसाय पर नियंत्रण प्रदान नहीं करता है।

विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम में संशोधन

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में भारत सरकार ने बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करेंगे और छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाएंगे।

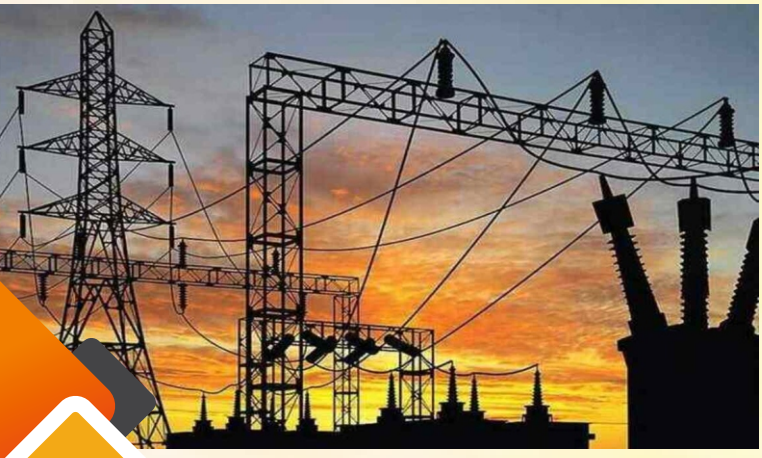

संबंधित प्रमुख बिंदु

- उपभोक्ताओं के परिसर में रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम स्थापित करने में आसानी बढ़ाने और तेजी से स्थापना की सुविधा के लिए नियमों में संशोधन किए गए हैं। 10 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता से छूट दी गई है। 10 किलोवाट से अधिक क्षमता की प्रणालियों के लिए, व्यवहार्यता अध्ययन को पूरा करने की समयसीमा को बीस दिन से घटाकर पंद्रह दिन कर दिया गया है। इसके अलावा, वितरण लाइसेंसधारकों के लिए रूफटॉप सोलर पीवी सिस्टम चालू करने की समयसीमा तीस दिन से घटाकर पंद्रह दिन कर दी गई है।

- संशोधन बहुमंजिला फ्लैटों में रहने वाले उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन का प्रकार चुनने की सुविधा प्रदान करते हैं और आवासीय सोसायटियों में कॉमन एरिया और बैक-अप जनरेटर के लिए अलग बिलिंग की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
- संशोधनों में उपभोक्ताओं की शिकायतों के मामले में बिजली की खपत को जांचने के लिए वितरण कंपनी द्वारा चेक मीटर लगाए जाने का भी प्रावधान है।
- गौरतलब है कि 31 दिसंबर, 2020 को बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 जारी किया गया | इसके तहत पूरे भारत में विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए मानक निर्धारित किए गए। इन नियमों में बिलिंग, शिकायतें, मुआवजा और नए कनेक्शन की समयसीमा जैसे पहलू शामिल हैं। ये नियम

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

प्रोज्यूमर (ऐसे व्यक्ति जो उपभोग और उत्पादन दोनों करते हैं) द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए भी सहायता प्रदान करते हैं।

एनटीपीसी-आरईएल की पहली सौर परियोजना

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में राजस्थान के छत्तरगढ़ में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (NTPC-REL) की पहली सौर परियोजना ने 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक संचालन कार्य शुरू करने की घोषणा की है। इसके साथ ही एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित क्षमता 73,958 मेगावाट तक पहुंच गई है।
- वर्तमान में, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की 17 परियोजनाएं क्रियान्वित हैं, जिनकी कुल क्षमता 6,000 मेगावाट से अधिक है। इसके साथ ही एनटीपीसी समूह की कुल नवीकरणीय ऊर्जा परिचालन क्षमता 3,448 मेगावाट हो गई है।
- छत्तरगढ़ सौर परियोजना की निर्धारित पूर्ण क्षमता 150 मेगावाट है और इसके मार्च 2024 तक पूरी तरह से क्रियान्वित होने की आशा है।
- यह परियोजना प्रति वर्ष 370 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए शुरू की गई है, जो 60,000 घरों के लिए पर्याप्त है, साथ ही हर साल 3 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन की बचत और 1,000 एमएमटीपीए पानी का संरक्षण भी करती है।

एनटीपीसी के बारे में

- एनटीपीसी लिमिटेड 74 गीगावॉट क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली ईकाई है जो भारत में उत्पादित कुल बिजली का 25% योगदान देती है।
- ध्यान रहे, वर्ष 2032 तक एनटीपीसी अपनी गैर-जीवाश्म-आधारित बिजली क्षमता को कंपनी के पोर्टफोलियो के 45%-50% तक विस्तार देना चाहता है। इसमें 130 गीगावॉट के कुल पोर्टफोलियो के साथ 60 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता शामिल होगी।
- एनटीपीसी ने भारत के नेट जीरो प्रयासों को मजबूती देने के लिए नीति आयोग के साथ साझेदारी की है।
- एनजीईएल एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका लक्ष्य एनटीपीसी की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा का ध्वजवाहक बनना है।

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)

इसकी परिचालन ग्रीन एनर्जी कैपिसिटी 3.4 गीगावॉट से अधिक है और 26 गीगावॉट प्रक्रिया में है, जिसमें 7 गीगावॉट का परिचालन शुरू होने वाला है।

सौर ऊर्जा से संबंधित सरकार की पहलें

- सोलर पार्क योजना (Solar Park Scheme): सोलर पार्क योजना विभिन्न राज्यों में लगभग 500 मेगावाट क्षमता के कई सोलर पार्क स्थापित करने पर लक्षित है। भारत में 37.49 गीगावॉट की कुल क्षमता वाले 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है।
- रूफटॉप सोलर योजना (Rooftop Solar Scheme) : इस योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा का दोहन करना है।
- राष्ट्रीय सौर मिशन (National Solar Mission): यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौती को संबोधित करते हुए पारिस्थितिक रूप से सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार और राज्य सरकारों की एक प्रमुख पहल है।
- सृष्टि योजना : (SRISTI: Sustainable rooftop implementation of Solar transfiguration of India) योजना भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने पर लक्षित है।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance- ISA) : अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्राँस द्वारा सह-स्थापित सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के वितरण में वृद्धि के लिये एक सक्रिय तथा सदस्य-संचालित एवं सहयोगी मंच है।
- किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड सौर पंपों की स्थापना का समर्थन करने और ग्रिड से जुड़े क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिये पीएम-कुसुम योजना कार्यान्वित की जा रही है।

राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन -2024

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एस.पी. सिंह बघेल ने नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन -2024 का उद्घाटन किया।

- यह तीन दिवसीय सम्मेलन 23 से 25 फरवरी 2024 तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर की एक पहल है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक सहयोगी शिक्षण मंच बनाना है।
- सम्मेलन स्वास्थ्य नीति निर्माताओं और कार्यान्वयनकर्ताओं के विचारों पर केंद्रित है, जो प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधन में योगदान देता है।
- यह राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), तपेदिक और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने जैसी स्वास्थ्य प्राथमिकताओं को संबोधित करने में नवीन दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है, जिसमें जूनोटिक रोगों, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के पहलुओं सहित एक स्वास्थ्य के लिए सहयोग पर जोर दिया गया है।
- यह आयोजन सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफ़ॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे उन्नत उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों के बारे में भी पता लगाएगा।

GS Foundation Batch UPSC & BPSC, Starting from 23rd February (English & Hindi Medium)